प्राक्कथन

रिज़र्व बैंक ने 2005 में अपने अस्तित्व के उल्लेखनीय सत्तर वर्ष पूरे किए। यह विकासशील देशों के कुछ सबसे पुराने केंद्रीय बैंकों में से एक है। इस अच्छी खासी लंबी अवधि में बैंक ने आकार और विविधता के दृष्टिकोण से बहुत विकास किया है और अपने संगठन तथा प्रबंध की कायापलट भी करता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में, मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट, 2004-05 की थीम 'भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास' रखना उचित समझा गया है। संयोगवश मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट का यह खंड उसी समय विमोचित किया जा रहा है जब कि 1967-1981 की अवधि से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास के तीसरे खंड का विमोचन हो रहा है।

थीम आधारित रिपोर्ट प्रकाशित करने की वर्ष 1998-99 में की गई शुरुआत से लेकर अब तक आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग ने भारत से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों को समाहित करते हुए छह रिपोर्टें जारी की हैं। तथापि, वर्तमान रिपोर्ट पिछली अन्य रिपोर्टों से इस मायने में अनोखी है कि इसमें विश्वभर में हुए केंद्रीय बैंकिंग के विकास के संदर्भ में पिछले सत्तर वर्ष से अधिक समय में रिज़र्व बैंक के विकास को विश्लेषित करते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि सत्तर वर्ष से अधिक समय के रिज़र्व बैंक के विकास की अवधारणा को इस प्रकार के वार्षिक प्रकाशन में भली भांति विश्लेषित करना संभव नहीं है, फिर भी, रिज़र्व बैंक के विस्तृत कार्य क्षेत्र के बहु आयामी फलक को समेटने का गंभीर प्रयास किया गया है।

उनकी संबंधित वित्तीय प्रणालियों तथा आर्थिक विकास के चरणों के विकास के साथ-साथ केंद्रीय बैंकों के कार्यों की उल्लेखनीय रूप से कायापलट हो गई है। केंद्रीय बैंकों ने विशेषज्ञता के भंडार के रूप में सेवा की है जिसका लाभ सामान्यतः सरकारों और संस्थाओं द्वारा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में, लिया गया है। समझा जाता है कि सभी देशों में केंद्रीय बैंक का सदैव केंद्रीभूत स्थान रहा है। बदलते माहौल की पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक भी 1935 में अपनी शुरुआत से ही मौद्रिक और वित्तीय नीतियां बनाने के साथ-साथ लगातार अपनी कायापलट करता रहा है। रिज़र्व बैंक के कार्य उसे सौंपे गए विविध प्रकार की भूमिकाओं का परिणाम हैं। इस संदर्भ में, इस रिपोर्ट में जिन प्रमुख कार्यों की जांच पड़ताल की गई है वे हैं- विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय बाज़ारों का विकास, मुद्रा संबंधी और राजकोषीय विचार विमर्श और तुलन पत्र के आयाम। पिछले साल की मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट की थीम मौद्रिक नीति का विकास थी इसलिए इस रिपोर्ट में उस बारे में विस्तार पूर्व चर्चा नहीं की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालनों में, घरेलू ज़रूरतों और अनिवार्यताओं के अनुसार परिवर्तनशील रहने के लिए बहुत लचीलापन है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ उपयुक्त ढंग से तालमेल रखने हेतु विनियमन और पर्यवेक्षण में संशोधन के प्रयास किए जाते रहे। रिज़र्व बैंक विकासशील सुदृढ़ वित्तीय बाज़ारों और वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा के अनुरूप अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और लिखतों में निरंतर रूप से परिष्कार लाने के लिए प्रयासरत रहा है। रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाज़ार और सरकार द्वारा ली गई उधार राशियों के प्रबंध में वर्षों से तकनीकी विशेषज्ञता अर्जित कर ली है। इससे इसे सरकार की उधार लेने की अपेक्षाओं और बाज़ार प्रत्याशा की पूर्ति के साथ-साथ ऋण और मुद्रा प्रबंध की दोहरी ज़िम्मेदारी दक्षतापूर्वक निभाने की क्षमता हासिल हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कायापलट के साथ ही रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में पिछले सात दशकों में बुनियादी बदलाव आया है। हाल के वर्षों में, विदेशी आस्तियों का तुलनात्मक महत्व बढ़ गया है और घरेलू आस्तियों का महत्व घट गया है। बासेल बासल

रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सत्तर वर्ष में इसके संगठनात्मक और प्रबंधकीय विकास तथा बैंक की बदलती भूमिका और कार्यों की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है।

रिपोर्ट का प्रारूप आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के नरेंद्र जाधव, प्रधान परामर्शदाता और मुख्य अर्थशास्त्री के समग्र मार्गदर्शन में विभाग के कोर दल द्वारा तैयार किया गया। कोर दल में के. उदय भास्कर राव, बलबीर कौर, एस. एम. पिलै, आशा कन्नन, गुणजीत कौर, निशिता राजे और डी. बोस शामिल थे। रिपोर्ट का प्रारूप लिखने में ए. करुणागरन, जे. के. मलिक, सिद्धार्थ सान्याल, रमेश गोलैत, एल. लक्ष्मणन, दीपा राज, इंद्रनील भट्टाचार्य, एस. सूरज, एस. एम. लोके, स्नेहल हेरवाडकर, संगीता मिश्रा, सत्यानंद साहू, अमरनाथ यादव, जय चंदर, राजीव जैन, राज राजेश, ए. के. शुक्ला, पंकज कुमार, पी. के. भोइटे और एस. के. टकले द्वारा व्यापक रूप से सहायता की गई।

रिपोर्ट लिखने के दौरान विभिन्न चरणों में संबंधित जानकारी देने में विभाग के अंदर एम. आर. नायर, आर. के. पट्टनायक, जनक राज, चरण सिंह, पार्थ रे और सुनंदो रॉय एवं विभाग के बाहर, मानव संसाधन विकास विभाग के संदीप घोष और बाज़िल शेख; बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के के. जी. गोपालकृष्ण, के. वी. सुब्बा राव, अमरेंद्र मोहन और पी. रविमोहन ने मूल्यवान एवं उल्लेखनीय योगदान दिया।

परिचालन संबंधी विभागों, नामतः, मानव संसाधन विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विधि विभाग और सरकारी और बैंक लेखा विभाग योगदान के लिए प्रशंसा योग्य हैं। आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग का लगभग प्रत्येक अधिकारी रिपोर्ट के दूसरे अध्याय - 'नवीनतम आर्थिक गतिविधियां' को तैयार करने के काम से जुड़ा रहा।

कोर दल को श्री एस. एस. तारापोर, डॉ. ए. वासुदेवन और प्रो. दिलीप नाचाने के साथ चर्चा का भी लाभ मिला।

भारत में केंद्रीय बैंकिंग के विकास का पता लगाना कठिन काम रहा है। हमारा प्रयास रिज़र्व बैंक के अवधारणामूलक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना रहा है क्योंकि देश की स्वतंत्रता और भारत में आर्थिक और वित्तीय विकास के विभिन्न चरणों में यह बदलता रहा है। इसके अस्तित्व के सत्तर वर्ष के दौरान के इसके कार्य की समीक्षा करना, एक विशेषता सदैव बरकरार रही है : वह है बदलती परिस्थितियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुभवों के अनुसरण में लगातार कायापलट करते रहना। अन्य केंद्रीय बैंकों में इधर कुछ वर्षों में बहुत भारी परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से होने वाली कायापलट के साथ, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांति-प्रगति और अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते हुए खुलेपन के परिप्रेक्ष्य में, भविष्य में निरंतर परिवर्तन जारी रहेगा।

मैं इस अवसर पर रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के प्रोफ़ेशनल कौशल और उनकी अत्यंत समर्पण की भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ जिनके बिना इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव नहीं था।

राकेश मोहन
उप गवर्नर

18 मार्च 2006